अर्थव्यवस्था को आठ बूस्टर डोज

स्वास्थ्य, पर्यटन व छोटे उद्योगों को रियायतें

कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को 1.1 लाख करोड़ की कर्ज गारंटी, बढ़ाई गई आपात ऋण सुविधा गारंटी

एमएसएमई को कर्ज के लिए 1.5 लाख करोड़ और मिलेंगे, 25 लाख छोटे कारोबारियों को लाभ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से पस्त अर्थव्यवस्था के प्रभावित क्षेत्रों को राहत टीके की आठ बूस्टर खुराकें दी हैं। स्वास्थ्य समेत प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की कर्ज गारंटी योजना का एलान किया। वहीं, बार-बार लॉकडाउन से हिचकोले खा रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ किया गया। क्रेडिट गारंटी योजना के तहत भी अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। इससे 25 लाख छोटे कारोबारियों को फायदा होगा।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोत्साहन पैकेज में सोमवार को छोटे कारोबारियों के साथ गरीबों, किसानों, बेरोजगारों को भी राहत और महामारी से बुरी तरह प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को सहारा देने की कोशिश की। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के बीच स्वास्थ्य ढांचे के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया है। वित्तमंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आठ उपायों के अलावा भी अन्य कदम उठाए गए हैं। सरकार का दावा है, अब तक 6,28,993 करोड़ के राहत उपाय किए हैं। कुछ नई योजनाएं हैं, तो कुछ पुरानी योजनाओं को विस्तार दिया गया है। ब्यूरो

प्रोत्साहन पैकेज का एलान करतीं वित्तमंत्री निर्मला।

पीएम गरीब कल्याण अनाज योजना

1 26 मार्च 2020 को योजना की घोषणा हुई थी। कोरोना प्रभावित गरीबों को पांच किलो राशन मुफ्त मिलता है। दूसरी लहर में मई 2021 में योजना फिर लॉन्च। करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा। 20-21 में 1,33,972 करोड़ रुपये खर्च हुए, इस साल 93,869 करोड़। कुल 2,27,841 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पर्यटन : गाइड और एजेंसी को कर्ज

2 11,000 से ज्यादा पंजीकृत टूरिस्ट गाइड को एक लाख और पर्यटन एजेंसी को 10 लाख तक का कर्ज मिलेगा। 100% गारंटी देगी। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं।

5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा

देश में आने वाले पहले पांच लाख विदेशी पर्यटकों के वीजा मुफ्त जारी होंगे। योजना 31 मार्च, 2022 तक। इसके तहत 100 करोड़ की मदद। एक पर्यटक को एक बार ही लाभ।

बच्चों की सेहत पर फोकस : आईसीयू वेंटिलेटर बेड-एंबुलेंस बढ़ाए जाएंगे

3 बच्चों के लिए आईसीयू व वेंटिलेटर बेड, एंबुलेंस जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय, जिला और उप जिला स्तर पर ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। 23,220 करोड़ से सुधरेगा ढांचा। 31 मार्च 2022 तक यह पैसा खर्च किया जा सकेगा। बीते साल 15 हजार करोड़ खर्च किए गए।

स्वास्थ्य ढांचा : 50 हजार करोड़ अन्य क्षेत्रों को 60 हजार करोड़

4 शहरों में स्वास्थ्य ढांचे के लिए 50 हजार करोड़, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए 60 हजार करोड़ रुपये। चिकित्सा क्षेत्र को कर्ज गारंटी। 100 करोड़ तक कर्ज 7.95% ब्याज पर मिलेगा। अन्य क्षेत्रों के लिए ब्याज 8.25 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा।

कृषि : अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी

5 किसानों को 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। इसमें 9125 करोड़ सब्सिडी केवल डीएपी और 5,650 करोड़ रुपये सब्सिडी एनपीके पर दी गई है। रबी सीजन 2020-21 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। अब तक किसानों को 85,413 करोड़ सीधे दिए गए हैं।

ऑक्सीजन संयंत्र के लिए दो करोड़ तक का ऋण

6 पहले आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के लिए तीन लाख करोड़ की घोषणा थी। अब 1.5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। कुल 4.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। अब तक शामिल सभी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। क्रेडिट लाइन गारंटी 4.0 के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए दो करोड़ तक के लोन का प्रावधान था। इस पर 100 फीसदी गारंटी दी गई।

क्रेडिट गारंटी : छोटो कारोबारियों को भी 1.25 लाख तक लोन

7 इसके तहत छोटे कारोबारी, व्यक्तिगत गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों से 1.25 लाख रुपये तक कर्ज ले सकेंगी। इसमें 7500 करोड़ रुपये का प्रावधान। बैंक के एमसीएलआर पर अधिकतम दो फीसदी जोड़कर ब्याज लिया जा सकेगा। अवधि 3 साल होगी। सरकार गारंटी देगी। 89 दिन के डिफॉल्टर समेत सभी प्रकार के उधार लेने वाले इसके हकदार होंगे।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक साल बढ़ी

8 योजना अब 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी। कुल 22,810 करोड़ खर्च होंगे, 58.50 लाख कर्मियों को लाभ होगा। अब तक 21.42 लाख लाभार्थियों पर 902 करोड़ खर्च हुए हैं। योजना में सरकार 15 हजार से कम वेतन वाले कर्मियों व नियोक्ता की ओर से पीएफ भुगतान करती है।

पर्यटन व निर्यात में आएगी तेजी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा : कारोबार